

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 15 नवम्बर, 2011

विषय:- सच्चिदानन्द फाउन्डेशन, नई दिल्ली को मौजा कांसवाली कोटरी, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में, चिकित्सा/स्वास्थ्य (योगाश्रम एवं चिकित्सालय निर्माण) हेतु 1.922 है० भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-923/12 ए०-86 (2008-11)/डी०एल०आर०सी०, दिनांक-19.12.2009 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, सच्चिदानन्द फाउन्डेशन, नई दिल्ली को मौजा कांसवाली कोटरी, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में, चिकित्सा/स्वास्थ्य (योगाश्रम एवं चिकित्सालय निर्माण) हेतु 1.922 है० भूमि कय की अनुमति, चिकित्सा विभाग/आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सहमति/अनापत्ति एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(I) के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (योगाश्रम एवं चिकित्सालय निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।



- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र उपरोक्त प्रयोजनों हेतु ही किया जायेगा। इसके साथ ही, प्रस्तावित भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्यों हेतु किये जाने पर, उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।
- 8- दून घाटी महायोजना-2001 में निर्धारित भू उपयोग के अनुरूप ही, अनुमन्य निर्माण कार्य, दून घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से कराया जाये।
- 9- स्थल पर पहुंच हेतु, प्रस्तावित न्यूनतम 12.0 मीटर पहुंच मार्ग पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा तथा मार्ग के विकास में संस्था यथावश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
- 10- नेशनल बिल्डिंग कोड, 2005 के प्राविधानों के अनुसार, 80 शय्याओं के इण्टरमीडिएट अस्पताल (कैटेगरी B) हेतु, निर्धारित 1.00 है0 भूमि के मानक को दृष्टिगत रखते हुए, 1.922 है0 भूमि क्रय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, किन्तु स्थल पर निर्माण कार्य, आवास विभाग के अन्तर्गत प्रचलित बिल्डिंग बाईलाज के अनुरूप ही, प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा तथा क्षेत्र हेतु, यथावश्यक अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास कराया जायेगा।
- 11- संस्था द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात् बी0पी0एल0 कार्ड धारको को निशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- 12- संस्था द्वारा, आपदा प्रबन्धन, संक्रामक रोगों आदि की रोकथाम के लिए, राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- 13- संस्था द्वारा, राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कार्य किया जायेगा।
- 14- संस्थान की स्थापना, संचालन एवं प्रचार प्रसार संस्था को अपने संसाधनों से करना होगा तथा इसमें राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहृयता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
- 15- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 16- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 17- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

18- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

19- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1

(पी०सी० शर्मा)

प्रमुख सचिव।

पू०प०सं०-242/समदिनांकित 2011

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- ले० कर्नल श्री डी०वी० सिंह (सेवानिवृत्त), पुत्र स्व० श्री सच्चिदानन्द सिंह, 89/4, कृष्णानगर, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली।
- 6- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(संतोष बडोनी)

अनुसचिव।